(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना के वर्तमान स्वरूप में पूर्णतया संतुष्ट है; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एम० पटेल): (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) एक चालू योजना है। इसके कार्यान्वयन की नीति को पिछले अनुभवों तथा विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर संशोधित किया जाता है। 1990–91 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो मुख्य सुधार किए गए है व इस प्रकार हैं:–अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये भौतिक लक्ष्यों को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये लक्ष्यों को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित किए गए हैं; अनुसूचित जाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के समकक्ष लाने के लिये उनके लिये अनुदेय सबसिडी को 5000/– रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर 50 प्रतिशत कर दिया गया है; ऋण समिति को समाप्त करने तथा क्रमबद्ध रूप से नकद राशि का वितरण करने का निर्णय लिया गया है; भूमि की खरीद को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनुमेय गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। इस योजना में आवश्यक सुधार लाने के लिये इसका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देश की विख्यात अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से एक समवर्ती मूल्यांकन कराया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर (जनवरी–दिसम्बर, 1989) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर सहायता प्राप्त 28 प्रतिशत लाभार्थियों ने 6400/– रुपये की गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

मूल्य-नियंत्रण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं को शामिल किया जाना

392. **श्री राम जेटमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करके इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ और आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुदीन अहमद): (क) पिछले दो महीनों (मई और जून, 1991) के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक का रुख मिला-जुला रहा है। इनमें से कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, मांग व पूर्ति में अन्तर, मौसमी कारणों तथा कुल मुद्रा-पूर्ति में बढ़ोतरी के कारण हुई कही जा सकती है।

(ख) से (घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता

दे रखी है। मुद्रा-पूर्ति को नियंत्रित करने, व्यय में मितव्ययिता बरतने, शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं के आपूर्ति और मांग प्रबंध को सुनिश्चित करने के कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मूलत: लागू करते हैं, समय-समय पर अन्य बातों के साथ यह सलाह दी है कि वे उन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्र खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनायें जहां अब तक ऐसे केन्द्र नहीं हैं अथवा कम संख्या में है; सम्पूर्ण आबादी को राशन कार्ड जारी करें तथा अपनी तरफ से आम खपत की और वस्तुएं इसके द्वारा वितरित करें।

उर्वरकों का उपयोग

393. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उर्वरकों के उपयोग में भी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश में उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) उर्वरकों की शेष मात्रा के आयात के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 में कुछ अनुमानों पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन और खपत का आकलन निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख मी. टन में)

	एन	पी	के	योग
खपत . .	81.44	36.47	14.35	135.26
उत्पादन . .	72.00	22.00	—	94.00

(ग) उर्वरकों की आवश्यकता को वर्ष के प्रारंभ में प्रयोग में नहीं लाये गये अवशेष भंडार और स्वदेशी उत्पादन तथा आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। पोटैशिक और गैर-पोटैशिक उर्वरकों के आयात के लिए व्यवस्था शुरू कर दी गयी है। एम.एम.टी.सी. ने जोकि इस उद्देश्य के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, आयात के लिए ठेकों को अंतिम रूप देना आरंभ कर दिया है।

पूरे वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले उर्वरकों की यथार्थ मात्रा अभी पूर्णत: निश्चित नहीं की गयी है।

भारतीय उर्वरक निगम को हुआ घाटा

394. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990-91 के वर्ष के दौरान भारतीय उर्वरक निगम को कुल 200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;